P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-4*(Supplementary Issue) July- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

ई गवर्नेस की अवधारणा, उपयोगिता एवं चुनौतियाँ

नागरत्ना गनवीर
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शा.शिवनाथ विज्ञान
महाविद्यालय,
राजनांदगांव

आबेदा बेगम
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शा.कमला देवी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
राजनांदगाँव

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र ई गवर्नेस की अवधारणा, उपयोगिता एवं चुनौतियों पर आधारित है। ई गवर्नेन्स का मुख्य कार्य भ्रष्टाचार विहीन पारदर्शिता पूर्ण ढंग से शीघ्र कार्य का निर्माण करना है। इंटरनेट के माध्यम से सरकारी सुविधाओं और योजनाओं को आम जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसे ही ई गवर्नेस, ई सरकार या डिजिटल सरकार के नाम से जानते हैं। ई गवर्नेस के द्वारा नागरिकों और व्यापारियों को सरल सुगम और महत्वपूर्ण योजनाये प्राप्त होती हैं। ई गवर्नेस के द्वारा अनेक योजनायें बनाई गई है जैसे–ई सेवा, ई नागरिक सेवा, ई चौपाल, ई बुक, ई पोस्ट पेमेंट बैंक इत्यादि।

मुख्य शब्द : ई गवर्नेस, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

प्रस्तावना

ई गवर्नेस को इलेक्ट्रानिक गवर्नेस, डिजिटल सरकार या ऑनलाइन सरकार के नाम से जानते हैं। इंटरनेट के जरिए सरकारी सूचनाओं एवं सुविधाओ को आम जनता तक पहुचाना ही ई गवर्नेस है। आम आदमी की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने यह तर्क संगत कुशल, पारदर्शी और विश्वसनीय सेवा है। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी.ए.आर. एण्ड पी.जी.) द्वारा राष्ट्रीय ई शासन योजना (एन.ई.जी.पी.) का प्रारंभ किया गया। केन्द्र सरकार ने 18 मई 2006 को 27 मिशन मोड परियोजनाओं और 10 घटकों के साथ एन.ईजी.पी. का अनुमोदन किया।

भारत में 1987 से निकनेट (उपग्रह आधारित कम्प्यूटर नेटवर्क) ईप्रशासन पर मुख्य बल दिया गया, बाद में सभी जिलो कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण करने राष्ट्रीय सूचना विभाग केन्द्र की सूचना प्रणाली की शुरूआत की गई। 1990 में राज्य की राजधानियों से लेकर सभी जिला मुख्यालयों तक इंटरनेट से जोड़ा गया। स्त्रोत India.govt.in

ई गवर्नेस को सरकार के द्वारा लोगों के हित के लिए बनाया गया है। जिसका मूल मंत्र है – ''एक कदम आपकी और एक कदम आपके लिये।''

अध्ययन का उद्देश्य

आम आदमी को ई गवर्नेस का अधिक से अधिक उपयोग करने व काम को शीघ्र करने, भ्रष्टाचार से मुक्त रहने की जानकारी तथा आम जनता को डिजिटल सेवा से परिचित करना।

ई गवर्नेस के लाभ या उपयोगिता

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिको, व्यापारियों और समाज के प्रत्येक वर्ग को सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएँ प्रदान कर रहे है। अब लोगो को सरकारी दफ्तररों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं हैं। वो घर बैठे सारा काम आसानी से कर सकते है। उदा. बैंक में खाता खुलवाना, पैसा जमा करना, सभी तरह के बिल भुगतान (बिजली बिल, पानी का बिल, टैक्स इत्यादि) इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से कर सकते हैं।

सभी तरह की टिकट बुकिंग, एयर, रेल्वे, बस, टैक्सी, होटल, इत्यादि। सभी तरह की खरीदी ऑन लाइन शॉपिंग के द्वारा की जा रही है। पेमेंट–क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटियम से कर सकते है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य लेन देन सभी ऑन लाइन हो गया है। नौकरी के लिए आवेदन, विद्यार्थी ऑन लाइन प्रवेश हेतु फार्म, रिजल्ट सब घर बैठे कर सकते है।

ई गवर्नेन्स का उद्देश्य

1. भारत को इलेक्ट्रानिक अर्थव्यवस्था में बदलना
2. भ्रष्टाचार कम करना
3. सरकारी कार्यो में गति लाना
4. आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना, शीघ्र सरल सुविधा देना

5. जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता लाना
6. आर्थिक विकास दर में वृद्धि करना।
7. पर्यावरण के लिए लाभदायक
8. जवाबदेही निश्चित करना।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केन्द्र सरकार ने गांवो और पंचायतो तक ई क्रांति का लाभ पहुचाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत इन्दिरा आवास, मनरेगा, समेत स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधित योजनाओं का लाभ इलेक्ट्रानिक के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। शहरों से गांवो की दूरी कम करने सभी तरह के केन्द्र राज्य सरकार की सूचना देने सभी गांवो की पंचायतो का ब्राडबैंड से जोड़ने कहा गया है। सरकार ने जनता से संपर्क करने एवं कार्यो को सरल बनाने के लिये ई गवर्नेन्स की कुछ श्रेणियाँ बनायी है, जिससे आम नागरिको को लाभ हो रहा है। इसके अलावा केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से सीधा संपर्क कर रही है और राज्यों के कार्यो व गतिविधियों के बारे में जानकारी ले रही है।

ई गवर्नेन्स की श्रेणियाँ

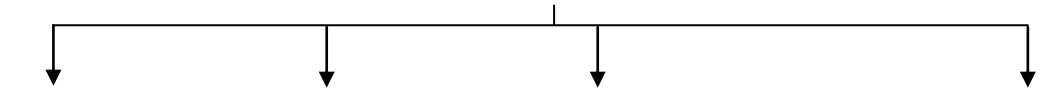

जी.टू.जी.(सरकार से सरकार तक)

इसके माध्यम से ई गवर्नेंस मे एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग से संपर्क कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। उदा.–किसी अपराधी के बारे में राज्य पुलिस विभाग को जानकारी मिली है तो वह संपूर्ण जानकारी सिस्टम में डाल देता है। उस अपराधी के बारे में देश के हर पुलिस स्टेशन में यह रिकार्ड आसानी से उपलब्ध हो जाता हैं, जिससे अपराधी को कहीं भी पकड़े में आसानी होती है।

इसी प्रकार भारत सरकार राज्य सरकारो को कोई जानकारी देना चाहे तो वेबसाइट पर जानकारी डाल देती है। सभी राज्य सरकार सूचना प्राप्त कर लाभ उठती है।

जी.टू.सी.(सरकार से नागरिक तक)

एक आम नागरिक इसकी सहायता से अपने सरकारी कार्यों को आसानी से पूरा कर सकता है। उदा.– बीमा पालिसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लाभ उठा सकता है। जी.पी.एफ., ई.पी.एफ. सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

जी.टू.बी.(सरकार से व्यवसाय तक)

व्यापारी वर्ग को ई गवर्नेन्स की सुवधिा प्राप्त है। वह घर बैठे कई सरकारी कार्यों को आसानी से कर सकता है जैसे– ट्रेडिंग, लाइसेंस के लिये आवेदन वैट के लिए पंजीकरण इत्यादि।

जी.टू.ई.(सरकार से कर्मचारी तक)

इसमें सरकार सरकारी कर्मचारी से आसानी से संपर्क कर सकती है। सरकार को किसी भी विभाग से जुड़े कर्मचारी की जानकारी उस विभाग के वेबसाइट के जरिये आसानी से प्राप्त हो सकती है। यह सरकार और कर्मचारी के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क करती है।

सी.टू.सी.(नागरिक से नागरिक तक)

इस प्राकर की ई सेवा में नागरिको का पारस्परिक संपर्क होता है। इन श्रेणियों का विकास कर सरकार, ई सेवा के माध्यम से एक ओर–प्रशासन को सशक्त, प्रभावशाली, पारदर्शी बना कर देश के आर्थिक सामाजिक विकास को द्रुत गति से आगे ले जाना चाहती है, वही दूसरी ओर आम जनता के जीवन को ई सेवा से सरल व सुगम बनाना चाहती है। यह देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

ई गवर्नेन्स की चुनौतियाँ

ई गवर्नेन्स सरकारी काम काज को गति प्रदान करने का बहुत सरल सुगम तरीका है किन्तु इसे चलाने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हैं :–

1. वेबसाइट की हैकिंग।
2. इंटरनेट की सुविधा सही न होना।
3. फर्जीकाल द्वारा खाते से पैसा निकालना।
4. आधारकार्ड का बचत खाते से जोड़ेने से जानकारी लिक होने का डर।
5. गाँवो में अशिक्षा, इलेक्ट्रानिक उपकरण का ज्ञान न होना।
6. गरीबी के कारण इलेक्ट्रानिक उपकरण न होना (उदा. मोबाईल, कम्प्यूटर नेट इत्यादि)।
7. सूचना क्रांति का ग्रामीण निर्धनों पर अल्प प्रभाव।

सूचना प्रौघोगिकी को जनसाधारण तक पहुंचाने, योजनाओं को शीघ्र लागू करने, दस्तावेजों को सुव्यवस्थित साफ्टवेयर में रखने, गांवो से शहरो की दूरी मिटाने में ई गवर्नेस एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सेवा हैं। इसमें सरकार व जनता दोनो सक्रिय रूप से भागीदारी होना चाहिए। आज के बदलते परिवेश में जहां ई–गवर्नेस से बहुत लाभ हो रहा हैं वहीं कुछ समस्यायें चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होते दिख रहा है परन्तु अपराधों पर नियंत्रण लाने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत हैं। जनता कों सचेत हो कर सभी कार्य करने की जरूरत हैं। सरकार की सुविधाओं का सही इस्तेमाल करें ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *योजना नवम्बर 2013 – पृ. 31–34*
2. *डॉ. फडिया बी.एल. , लोक प्रशासन, साहित्य भवन आगरा 2009 पृ. 950*
3. *योजना नवम्बर 2014 डिजिटल डेमोक्रेसी*
4. *मिश्र उमाशंकर – डिजिटल डेमोक्रेसी और पत्राचार योजना नवम्बर 2014*
5. *राष्ट्रीय पोर्टल–20, इंटरनेट से प्राप्त आंकडे*